NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-11-2024

विषय सूची

जनसंख्या में गिरावट की लागत?

सीसे के प्रदूषण (Lead Exposure) के कारण $6 ट्रिलियन की आर्थिक हानि

स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर [State of Food and Agriculture (SOFA)] 2024: FAO

यूरोप का डिजिटल यूरो

RBI द्वारा FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए नया फ्रेमवर्क जारी

भारत का पहला आकाशीय रक्षा अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास (Antariksha Abhyas)

शहरों के सतत विकास में AI

संक्षिप्त समाचार

आचार्य कृपलानी

मौलाना अबुल कलाम आजाद

असम में कॉमिक्स कमांडो (Comics Commandos in Assam)

अंतर-राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया

गोट्टी कोया जनजातियाँ (Gotti Koya Tribals)

थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा [Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)]

NGOs का FCRA लाइसेंस निरस्तीकरण

सेवा कार्यक्रम के रूप में EV

होकरसर आर्द्रभूमि (Hokersar wetland)

डिक्लिपटेरा पॉलीमोर्फा (Dicliptera Polymorpha)

जनसंख्या में गिरावट की लागत?

सन्दर्भ

- भारतीय राज्यों में विभिन्न जनसांख्यिकीय रुझान उनके व्यापक निहितार्थों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न करते हैं।

भारत में जनसांख्यिकीय रुझान

- **कुल प्रजनन दर (TFR):** 2019 और 2021 के बीच, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने 1.5 की TFR दर्ज की।
  - इसके विपरीत, बिहार (3), उत्तर प्रदेश (2.7) और मध्य प्रदेश (2.6) में प्रजनन दर अधिक थी।
  - स्थिर जनसंख्या को बनाए रखने के लिए 2.1 का TFR प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है।
- **वृद्ध जनसंख्या चिंताएँ:** इंडिया एजिंग रिपोर्ट (UNFPA) के अनुसार भारत में वृद्ध जनसंख्या 2021 में 10.1% से बढ़कर 2036 तक 15% होने का अनुमान है।
  - केरल में वृद्ध जनसंख्या 16.5% है जबकि बिहार में यह 2021 में 7.7% है।

वृद्ध होती जनसंख्या के निहितार्थ

- **आर्थिक निहितार्थ;**
  - वृद्ध जनसँख्या में वृद्धि के साथ पेंशन पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि।
  - **वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात:** कार्यशील आयु (18-59 वर्ष) के प्रत्येक 100 लोगों के लिए वृद्ध वयस्कों की संख्या को दर्शाता है। 15% से अधिक अनुपात वृद्धावस्था संकट का संकेत देता है। कुछ दक्षिणी राज्य पहले ही इस बेंचमार्क को पार कर चुके हैं।
  - **उपभोक्ता मांग में कमी:** वृद्ध जनसँख्या युवा, अधिक सक्रिय जनसांख्यिकी की तुलना में कम उपभोग करती है।
  - **स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे पर दबाव:** 2017-18 में, दक्षिणी राज्यों ने भारत की कुल जनसँख्या का केवल पाँचवाँ भाग होने के बावजूद हृदय रोगों पर कुल व्यय का 32% भाग लिया।
- **राजनीतिक निहितार्थ;**
  - **अंतरराज्यीय संसाधन तनाव:** दक्षिणी राज्य, कर राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, धीमी जनसंख्या वृद्धि के कारण केंद्रीय संसाधनों का घटता हुआ हिस्सा प्राप्त करते हैं।
  - **परिसीमन और प्रतिनिधित्व:** 2026 में संसदीय सीटों पर रोक की समाप्ति के बाद एक नया परिसीमन अभ्यास शुरू होगा जो जनसंख्या परिवर्तनों से प्रभावित होकर लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व को परिवर्तित देगा।
- **सामाजिक निहितार्थ:** बढ़ती हुई बुजुर्ग जनसँख्या को सहारा देने का भार पीढ़ियों के बीच तनाव उत्पन्न कर सकता है।
  - साथ ही, समुदाय-आधारित देखभाल जैसी वैकल्पिक सहायता प्रणालियों की भी अधिक आवश्यकता होगी।

वैश्विक परिदृश्य

- जापान में औसत आयु 48 वर्ष से अधिक है। इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता बनी रही, कार्यबल में कमी आई और पेंशन तथा स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई।
- 1979 से 2015 तक लागू की गई चीन की एक-बच्चा नीति ने जन्म दर को काफी कम कर दिया, जिससे जनसंख्या तेज़ी से बूढ़ी हो रही है।

- 2022 तक दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है, जो 0.78 है।

आगे की राह

- **नीतिगत समायोजन:** नीतियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश के भुगतान के माध्यम से परिवारों का समर्थन करने और "मातृत्व दंड" को कम करने वाली रोजगार प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **लिंग समानता:** बेहतर लिंग समानता वाले राज्य और देश अधिक संधारणीय प्रजनन दर बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखती हैं तो वे बच्चे पैदा करने के लिए अधिक इच्छुक होती हैं।
- **रणनीतिक समर्थन:** आधुनिक सामाजिक-आर्थिक अपेक्षाओं के साथ संरेखित कार्य-परिवार नीतियों को लागू करना प्रजनन दरों का समर्थन करेगा और संतुलित जनसांख्यिकीय और आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा।

Source: TH

सीसे के प्रदूषण (Lead Exposure) के कारण $6 ट्रिलियन की आर्थिक हानि

सन्दर्भ

- द लांसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हालिया अनुमानों में वैश्विक स्वास्थ्य पर सीसे (सीसा) नामक एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन के प्रदूषण के गंभीर दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है।

सीसा (Pb) के बारे में

- **संक्षिप्त विवरण:** सीसा एक भारी धातु है और पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। यह नरम, लचीला होता है और इसका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है।
- **सीसे के प्रदूषण के स्रोत:** खनन, गलाने, विनिर्माण, पुनर्चक्रण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएँ।
  - उत्पाद उपयोग जैसे लेड-एसिड बैटरी (सबसे बड़ा उपभोक्ता), पेंट, पिगमेंट, सना हुआ ग्लास, सिरेमिक, गोला-बारूद।
  - पुरानी सीसा-आधारित पाइपलाइन से लीक होने से जल संदूषण।
- **स्वास्थ्य प्रभाव:** मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को हानि, संज्ञानात्मक क्षमताओं और गुर्दे की विफलता को कम करता है।
  - सीसे से हृदय संबंधी प्रभावों के कारण 2021 में 1.5 मिलियन से अधिक मृत्यु हुईं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** मिट्टी में सीसे की सांद्रता में 0 ppm से 1000 ppm तक की वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है

सीसा जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई

- सीसा जोखिम के लिए WHO नैदानिक प्रबंधन दिशानिर्देश।
- **सीसा पेंट (Lead Paint) को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन:** यह UNEP और WHO द्वारा बनाई गई एक स्वैच्छिक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य सीसा युक्त पेंट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को बढ़ावा देकर सीसा के प्रदूषण को रोकना है।
- सीसा युक्त पेट्रोल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।

Source: DTE

स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर [State of Food and Agriculture(SOFA)] 2024: FAO

सन्दर्भ

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 'स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर 2024' (SOFA 2024) जारी किया है।

स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर(SOFA) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र के FAO द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है जो वैश्विक खाद्य और कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर गहन विश्लेषण एवं अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- SOFA 2024 खाद्य पदार्थों की वास्तविक लागत पर गहनता से चर्चा करता है, तथा कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक समावेशी, लचीला और सतत बनाने की आवश्यकता पर बल देता है।
    - यह 2023 की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें कृषि खाद्य प्रणालियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए वास्तविक लागत लेखांकन के उपयोग की खोज की गई है।
    - SOFA 2023 ने कृषि खाद्य प्रणालियों में छिपी हुई लागतों और लाभों की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तथा इन छिपे हुए पहलुओं को प्रकट करने के लिए एक विधि के रूप में वास्तविक लागत लेखांकन का प्रस्ताव दिया।

मुख्य निष्कर्ष: स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर(SOFA) 2024

- **वास्तविक लागत लेखांकन:** रिपोर्ट में कृषि खाद्य प्रणालियों में वास्तविक लागत लेखांकन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
    - यह खाद्य उत्पादन और उपभोग से जुड़ी छिपी हुई लागतों और लाभों को प्रकट करने में सहायता करता है, जिसमें पर्यावरणीय गिरावट, स्वास्थ्य प्रभाव और सामाजिक असमानताएँ शामिल हैं।
- **वैश्विक संदर्भ:** कुल मिलाकर, कृषि खाद्य प्रणालियों की छिपी हुई लागतें लगभग $12 ट्रिलियन प्रति वर्ष हैं, 156 देशों को शामिल करते हुए विश्लेषण में पाया गया। वास्तव में, वैश्विक स्तर पर, प्रमुख मात्राबद्ध छिपी हुई लागतें अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न से उत्पन्न होती हैं जो बीमारियों और कम श्रम उत्पादकता का कारण बनती हैं।
    - भारत की छिपी हुई लागतें वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी हैं, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, जिनकी छिपी हुई लागतें क्रमशः $1.8 ट्रिलियन और $1.4 ट्रिलियन हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी लागतें:** स्वास्थ्य संबंधी छिपी हुई लागतें, जिसमें आहार संबंधी बीमारियों के कारण उत्पादकता में होने वाली हानियाँ शामिल हैं, कुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।
    - ये लागतें वार्षिक लगभग $846 बिलियन होने का अनुमान है, जो बीमारी के भार और कम श्रम उत्पादकता को दर्शाती हैं।
- **आहार जोखिम और गैर-संचारी रोग:** अस्वास्थ्यकर आहार वैश्विक छिपी लागतों में एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जो इन लागतों का लगभग 70% ($8.1 ट्रिलियन) है।
    - रिपोर्ट आहार जोखिमों और गैर-संचारी रोगों के बीच संबंध को रेखांकित करती है, और स्वस्थ खाद्य वातावरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव:** कृषि खाद्य प्रणालियाँ समाज के लिए महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न करती हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका नकारात्मक प्रभाव भी बहुत अधिक होता है।

  - रिपोर्ट इन छिपी लागतों की पहचान करती है, जिसमें बाजार और नीति विफलताओं से होने वाली आर्थिक हानि शामिल हैं, और नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए व्यापक आकलन की आवश्यकता पर बल देती है।
- **वैश्विक परिदृश्य और केस स्टडीज़:** रिपोर्ट वैश्विक परिदृश्य और केस स्टडीज़ प्रस्तुत करती है जो राष्ट्रीय कृषि खाद्य प्रणालियों के वांछित परिणामों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
  - ये परिदृश्य सतत और न्यायसंगत खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने के संभावित मार्गों को चित्रित करने में सहायता करते हैं।
- **उपभोक्ताओं और उत्पादकों की भूमिका:** रिपोर्ट कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने में उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है।
  - इसमें उपभोक्ताओं की अधिक जागरूकता और सहभागिता के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादकों की समान भूमिका की भी बात कही गई है।

प्रमुख अनुशंसाएँ (परिवर्तन के लिए नीतिगत हस्तक्षेप)

- **स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना:** प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और शर्करा के सेवन को कम करते हुए साबुत अनाज, फलों, सब्जियों और लाभकारी फैटी एसिड के सेवन को प्रोत्साहित करना स्वास्थ्य संबंधी लागतों को काफी कम कर सकता है।
- **संधारणीय कृषि पद्धतियाँ:** संधारणीय कृषि पद्धतियों को लागू करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और नाइट्रोजन अपवाह जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय छिपी लागतों को कम किया जा सकता है।
- **सामाजिक समानता में सुधार:** उचित वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के माध्यम से कृषि-खाद्य श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को संबोधित करने से सामाजिक छिपी लागतों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- इसमें संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, संस्थागत और वित्तीय क्षमताओं में सुधार करना एवं परिवर्तन प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल करना सम्मिलित है।

निष्कर्ष

- FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि-खाद्य प्रणालियों की 1.3 ट्रिलियन डॉलर की छिपी हुई लागत, व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को प्रकट करती है।
- स्वस्थ आहार, सतत कृषि पद्धतियों और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर, भारत इन छिपी हुई लागतों को काफी हद तक कम कर सकता है और एक स्वस्थ, अधिक संधारणीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

Source: DTE

यूरोप का डिजिटल यूरो

सन्दर्भ

- यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) अपनी डिजिटल मुद्रा के लिए परीक्षण चरण शुरू करने वाला है, इसका "तैयारी चरण(preparation phase)" 2023 में शुरू होगा।

डिजिटल यूरो

- डिजिटल यूरो नकदी का एक डिजिटल रूप होगा, जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाएगा और यह यूरो क्षेत्र में सभी के लिए उपलब्ध होगा, सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा।

- यह सभी यूरो क्षेत्र के देशों में सुलभ और स्वीकार्य होगा।
- यह मुद्रा क्रेडिट कार्ड, ऐप, क्रिप्टोकरेंसी और बैंक हस्तांतरण जैसे मौजूदा कैशलेस विकल्पों के लिए सरकार का विकल्प है।
- डिजिटल यूरो का उपयोग बैंक या भुगतान गेटवे को शामिल किए बिना, स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर डिजिटल वॉलेट से सीधे भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
- डिजिटल यूरो अन्य प्रकार के डिजिटल भुगतान विकल्पों से अलग है क्योंकि ECB इसे सीधे जारी करता है।

डिजिटल मुद्रा क्या है?

- डिजिटल मुद्रा किसी भी प्रकार के पैसे या मुद्रा को संदर्भित करती है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत और लेन-देन किया जाता है।
- सिक्कों या कागज़ के बिलों जैसी भौतिक मुद्राओं के विपरीत, डिजिटल मुद्राएँ पूरी तरह से डिजिटल रूप में उपस्थित होती हैं और इनका उपयोग ऑनलाइन लेनदेन के लिए किया जा सकता है।
- डिजिटल मुद्राओं के दो मुख्य प्रकार हैं:
  - **क्रिप्टोकरेंसी:** यह डिजिटल मुद्रा का एक विकेन्द्रीकृत रूप है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीकों का उपयोग करता है और ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करता है। उदाहरणों में बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल (XRP) और लिटकोइन शामिल हैं।
    - इसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, जो इसे पारंपरिक मुद्रा से अलग बनाता है।
  - **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC):** यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित मुद्रा का एक डिजिटल रूप है।
    - यह डिजिटल रूप में किसी देश की आधिकारिक मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है।
- **डिजिटल मुद्राएं विभिन्न लाभ प्रदान करती हैं:**
  - त्वरित लेनदेन,
  - कम लेनदेन शुल्क और
  - बिचौलियों के बिना वैश्विक लेनदेन करने की क्षमता।

भारत में डिजिटल मुद्रा

- भारत का डिजिटल रुपया, जिसे eRs या eINR भी कहा जाता है, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) है।
- RBI ने 2022 में भौतिक मुद्रा के डिजिटल समकक्ष ई-रुपी पायलट की शुरुआत की।
- RBI दो प्रकार की डिजिटल मुद्राओं की खोज कर रहा है:
  - **थोक CBDC (e₹-W):** इसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच अंतर-बैंक निपटान एवं भुगतान की दक्षता में सुधार करना है।
  - **खुदरा CBDC (e₹-R):** इसका उद्देश्य खुदरा लेनदेन के लिए आम जनता को लक्षित करना है, ठीक उसी तरह जैसे लोग आज भौतिक मुद्रा का उपयोग करते हैं।

विशेषताएँ

- यह भारतीय रुपये का टोकनयुक्त डिजिटल संस्करण है, जो ब्लॉकचेन या वितरित खाता प्रौद्योगिकी पर कार्य करता है।

- यह कानूनी निविदा के रूप में कार्य करता है, जिसे व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी निकायों द्वारा स्वीकार किया जाता है।
- इसे RBI की वित्तीय नीतियों के अनुसार जारी किया जाता है और इसे वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भौतिक नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।
- डिजिटल रुपये का उपयोग करने वाले लेन-देन पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों की तुलना में अधिक तेज़ी से और सुरक्षित रूप से संसाधित होते हैं।

महत्त्व

- **नकदी का प्रतिस्थापन:** जबकि UPI व्यक्तियों या व्यवसायों के बीच धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, e₹ का उपयोग खरीदारी से लेकर FD तक के लिए किया जा सकता है।
- **नियंत्रण:** e₹ को RBI द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ताकि इसका उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सके - जैसे कि सब्सिडी या अन्य खर्च, विशेष रूप से। यह प्रत्यक्ष हस्तांतरण होने की संभावना नहीं है जिसका दुरुपयोग हो सकता है।
- **कम लागत:** क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे ,मध्यस्थों को दरकिनार करके, ई-रुपी से लेनदेन शुल्क कम हो सकता है।
- **वित्तीय समावेशन:** केंद्रीय बैंक के साथ सीधे रखे गए ई-रुपी खाते पारंपरिक बैंकों तक पहुंच के बिना उन लोगों के लिए कम लागत या मुफ्त विकल्प प्रदान कर सकते हैं।

Source: TH

RBI द्वारा FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए नया फ्रेमवर्क जारी

सन्दर्भ

- यदि इकाई निर्धारित सीमा का उल्लंघन करती है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) द्वारा किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन ढांचा जारी किया।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान नियमों के तहत, FPI किसी भारतीय कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% भाग रख सकते हैं।
- पहले इस सीमा को पार करने पर FPI के पास दो विकल्प होते थे: अधिशेष शेयरों को बेचना या उन्हें FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

- FPI में दूसरे देश के निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।
- यह निवेशक को किसी कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है।
- FPI होल्डिंग्स में स्टॉक, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR), ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDR), बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) शामिल हो सकते हैं।
- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से अलग है, जो किसी विदेशी कंपनी या परियोजना में किसी अन्य देश के निवेशक, कंपनी या सरकार द्वारा किया गया स्वामित्व है।

नया फ्रेमवर्क

- **अनिवार्य सरकारी स्वीकृति:** जब FPIs की इक्विटी होल्डिंग्स निर्धारित 10% सीमा को पार कर जाती है, तो उन्हें सरकार से आवश्यक स्वीकृति लेनी चाहिए, जो FDI में पुनर्वर्गीकरण का संकेत है।
- **समय पर पुनर्वर्गीकरण:** RBI ने अनिवार्य किया है कि सीमा का उल्लंघन करने वाले लेनदेन की तारीख से पांच कारोबारी दिनों के अंदर पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
- अनुपालन आवश्यकताएँ;
  - निवेशों को वर्तमान नियमों के तहत प्रवेश मार्गों, क्षेत्रीय सीमाओं, निवेश सीमाओं, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों और अन्य FDI-विशिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए।
  - RBI विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण साधनों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 के अनुसार व्यापक रिपोर्टिंग के लिए कहता है।
- **संशोधित SEBI दिशानिर्देश:** SEBI के अनुसार पुनर्वर्गीकरण का विकल्प चुनने वाले FPIs को अपने संरक्षक को सूचित करना होगा, जो रूपांतरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रभावित कंपनी में किसी भी अन्य इक्विटी लेनदेन को अस्थायी रूप से रोक देगा।

नये फ्रेमवर्क का महत्व

- **विनियामक अनुपालन:** यह सुनिश्चित करता है कि FPI से FDI में संक्रमण की प्रक्रिया व्यवस्थित हो, जिससे विनियामक उल्लंघन न्यूनतम हो।
- **निवेश निरीक्षण:** यह भारतीय इक्विटी में विदेशी निवेश की बेहतर निगरानी करता है, पूंजी प्रवाह और राष्ट्रीय आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखता है।

Source: IE

भारत का पहला आकाशीय रक्षा अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास(Antariksha Abhyas)

समाचार में

- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) द्वारा आयोजित पहला अंतरिक्ष अभ्यास, 'अंतरिक्ष अभ्यास – 2024(Antariksha Abhyas – 2024)' नई दिल्ली में शुरू हो गया है।

रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) के बारे में

- 2018 में स्थापित, यह भारतीय सशस्त्र बलों की एक एकीकृत त्रि-सेवा एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है।
- इसका कार्य भारत के अंतरिक्ष-युद्ध और सैटेलाइट इंटेलिजेंस परिसंपत्तियों का संचालन करना है।

अभ्यास का महत्व/आवश्यकता

- अंतरिक्ष अभ्यास अपनी तरह का पहला अभ्यास है और इससे अंतरिक्ष में राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने और सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एकीकृत करने में सहयात प्राप्त होने की संभावना है।
  - आधुनिक रक्षा में अंतरिक्ष संपत्तियां आवश्यक हैं, लेकिन एंटी-सैटेलाइट हथियारों, साइबर हमलों और अंतरिक्ष मलबे जैसे खतरों के प्रति तेजी से संवेदनशील हैं।
- चूंकि अंतरिक्ष तेजी से भीड़भाड़ वाला, विवादित और प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, इसलिए अंतरिक्ष अभ्यास का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के मना या व्यवधान की स्थिति में संचालन के संचालन में कमजोरियों की पहचान करना है।

क्या आप जानते हैं?

- मार्च 2019 में, भारत ने मिशन शक्ति (एक एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण) का सफलतापूर्वक संचालन किया और पूर्ण स्वदेशी तकनीक के आधार पर बाहरी अंतरिक्ष में एक उपग्रह को रोकने और नष्ट करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
- इस परीक्षण के साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन से युक्त अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के एक विशेष समूह में शामिल हो गया।

Source: PIB

शहरों के सतत विकास में AI

सन्दर्भ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के उपयोग से भारतीय शहरों के सतत विकास और प्रबंधन में डेटा संग्रहण और समन्वय संबंधी कुछ मुख्य समस्याओं को हल करने में सहायता मिल सकती है।

परिचय

- भारत आर्थिक विकास के अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए अगले 20 वर्षों में इसके शहरों में लगभग 270 मिलियन नागरिक जुड़ने की संभावना है।
- इस तरह का तेज़ शहरीकरण चुनौतियाँ लेकर आएगा, जिसके लिए सतत विकास के मार्गों की पहचान करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार कर सके।
    - स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में एक विकसित राष्ट्र का सपना - प्रत्येक भारतीय के लिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) क्या है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है, यह ऐसी स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को मॉडल करने या उनमें सुधार करने की अनुमति देती है।
- स्व-चालित कारों के विकास से लेकर ChatGPT और Google के बार्ड जैसे जनरेटिव AI टूल के प्रसार तक, AI तेजी से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है - और एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रत्येक उद्योग निवेश कर रहा है।

सतत् विकास

- यह भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की अवधारणा को संदर्भित करता है।
- यह तीन महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच संतुलन पर बल देता है: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण।
- 2015 में, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जो 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से युक्त एक वैश्विक ढांचा है।

सतत विकास में AI की भूमिका

- **विकास के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण:** AI शहरी विकास पैटर्न का पूर्वानुमान लगा सकता है, जिससे योजनाकारों को ज़ोनिंग, बुनियादी ढाँचे के विकास और संसाधन आवंटन के बारे में डेटा-संचालित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी:** AI जैव विविधता, वन क्षेत्र और अन्य पर्यावरणीय संकेतकों की निगरानी करने, संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने तथा शहरों के अंदर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में सहायता कर सकता है।
- **प्रदूषण नियंत्रण:** AI-आधारित प्रणालियाँ वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगा सकती हैं और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय सुझा सकती हैं।
- **डेटा-संचालित शासन:** AI शहरी विकास, संसाधन उपयोग, प्रदूषण और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके सूचित निर्णय लेने में शहर की सरकारों की सहायता कर सकता है।
- **परिवहन:** सार्वजनिक परिवहन के लिए कार स्वामियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में दिखाई देने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि बस और मेट्रो रेल सेवाओं के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी निर्बाध और अनुमानित रूप से उपलब्ध हो।
- **इलेक्ट्रिक वाहन (EV) एकीकरण:** AI परिवहन नेटवर्क में इलेक्ट्रिक वाहनों के एकीकरण का प्रबंधन करने, चार्जिंग स्टेशनों, मार्ग नियोजन और ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने में सहायता कर सकता है।

सरकारी पहल

- **भारत में AI बनाएं:** सरकार ने 2023-24 की अपनी बजट घोषणा में 990 करोड़ रुपये के समग्र बजट के साथ कृषि, स्वास्थ्य और शहरी स्थिरता के क्षेत्रों में AI के लिए तीन केंद्रों के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 'भारत में AI बनाना और AI को भारत के लिए कार्य करना' है।
- 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन का लक्ष्य शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के साथ 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में विकसित करना है।
  - AI इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो शहरों को स्थिरता के मुद्दों को हल करने, संसाधनों का अनुकूलन करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में सहायता करता है।
- **इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा:** भारत इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है, और AI ईवी संचालन और बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

- भारत के सतत विकास की खोज में AI एक गेम-चेंजर सिद्ध हो सकता है, जो देश की सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत कर सकता है।
- भारत में तेजी से शहरीकरण, संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में AI स्मार्ट, कुशल एवं समावेशी सिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

आचार्य कृपलानी

समाचार में

- आचार्य कृपलानी की जयंती प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाई जाती है।

आचार्य कृपलानी के बारे में

- **जन्म और प्रारंभिक जीवन:** 1888 में हैदराबाद, सिंध (अब पाकिस्तान में) में जन्मे।
- **राष्ट्रवादी भागीदारी:** वे एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, सांसद और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार गांधीजी के संपर्क में आए।
- **गांधीवादी आंदोलन से जुड़ाव:** 1927 से गुजरात में आश्रम के काम में लगे रहे।
  - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक आंदोलनों में शामिल रहे।
- **"आचार्य" की उपाधि:** गुजरात विद्यापीठ में कार्य करते समय उन्हें "आचार्य" के नाम से जाना जाने लगा, यह उपाधि उनके जीवन भर उनके साथ रही।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका:** 1934 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में कार्य किया।
  - राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए कई बार गिरफ्तार हुए।
- **संविधान सभा:** 1946 से 1951 तक भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए।
- **स्वतंत्रता के बाद का राजनीतिक करियर:** 1954 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दे दिया।
  - इसके बाद एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्ति बने रहे।
  - 1952, 1957, 1963 और 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए।
- **मृत्यु:** 19 मार्च 1982 को निधन हो गया।

Source: PIB

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

सन्दर्भ

- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

परिचय

- मौलाना आज़ाद एक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे।
- उन्होंने मुसलमानों के बीच क्रांतिकारी भर्ती बढ़ाने के लिए 1912 में एक साप्ताहिक उर्दू पत्रिका अल-हिलाल की स्थापना की।
- 1920 में, उन्हें यूपी के अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नींव समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था।
- उन्हें दिल्ली में कांग्रेस के विशेष सत्र (1923) का अध्यक्ष चुना गया था।
- 35 वर्ष की आयु में, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने।
- विरासत: वे स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री भी थे और उन्हें देश की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आकार देने का श्रेय दिया जाता है।

- उनके कार्यकाल के दौरान, पहला IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई।
- संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद उनके कार्यकाल के दौरान स्थापित सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संस्थानों में से थे।

Source: IE

असम में कॉमिक्स कमांडो (Comics Commandos in Assam)

समाचार में

- असम के ग्वालपाड़ा जिले में 30 स्थानीय युवाओं का एक समूह, जिन्हें "कॉमिक्स कमांडो" कहा जाता है, बाल श्रम और बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए कॉमिक्स का उपयोग कर रहे हैं।

असम में कॉमिक्स कमांडो

- यह असम के ग्वालपाड़ा जिले के बालीजान ब्लॉक में एक शैक्षिक कार्यक्रम है।
- यह बाल श्रम और बाल विवाह से लड़ने के लिए कॉमिक्स का उपयोग कर रहा है।
- इसके तहत, 30 स्थानीय युवाओं को इन सामाजिक मुद्दों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कैरिकेचर और डूडल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

आवश्यकता और महत्व

- असम के शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल छोड़ने वालों की दर 2020-21 में 3.3% से बढ़कर 2021-22 में 6.02% हो गई है।
- गरीबी जैसे परिवारों पर आर्थिक दबाव के कारण स्कूल छोड़ने वालों की दर बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों को कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है या वित्तीय भार कम करने के लिए उनकी शादी कर दी जाती है।
- इसलिए, कहानी सुनाने में कॉमिक्स की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों और स्कूल समितियों की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया है
- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2023 में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2026 तक इसे समाप्त करना है, रिपोर्ट्स में उल्लेखनीय कमी दिखाई गई है, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

Source : TH

अंतर-राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया

समाचार में

- अंतर-राज्य परिषद, जो केन्द्र-राज्य तथा अंतर-राज्यीय समन्वय एवं सहयोग के लिए कार्य करती है, का पुनर्गठन किया गया है तथा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

अंतर-राज्यीय परिषद के बारे में

- **उद्देश्य:** नीतियों पर चर्चा को सुगम बनाना, अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाना, तथा राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर संघ और राज्यों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- **स्थापना:** यद्यपि अनुच्छेद 263 में ऐसी परिषद की संभावना प्रदान की गई थी, लेकिन केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा औपचारिक रूप से 1990 में ISC की स्थापना की गई थी।
- **संरचना:** प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  - सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं।
  - कुछ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विशेष रूप से अंतरराज्यीय मामलों से संबंधित मंत्री भी ISC का हिस्सा हैं।
- **कार्य:** नीति समन्वय, संघर्ष समाधान समीक्षा करना और राज्यों में प्रशासन एवं शासन को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें करना।

Source: BS

गोट्टी कोया जनजातियाँ (Gotti Koya Tribals)

समाचार में

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने केंद्र और राज्यों से गोटी कोया जनजातियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

पृष्ठभूमि

- माओवादी विद्रोह और सुरक्षा बलों एवं वामपंथी उग्रवादियों के बीच संघर्ष के कारण गोटी कोया अपने मूल छत्तीसगढ़ से विस्थापित हो गए थे।
- उन्हें अपने नए राज्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। इससे वन अधिकार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और आदिवासी लाभों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।

गुट्टी कोया जनजाति के बारे में

- वे आदिवासी जनजातियाँ हैं और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं।
- वे गोंडी बोलते हैं, जो दक्षिण-मध्य द्रविड़ भाषा है जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।
- उनका प्रकृति से गहरा आध्यात्मिक संबंध है।
- गोट्टी कोया गाँवों में एक पारंपरिक राजनीतिक संरचना है जिसका नेतृत्व पटेल नामक ग्राम प्रधान करता है।

Source: TH

थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा [Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)]

सन्दर्भ

- एक अध्ययन में सिनोवैक बायोटेक की निष्क्रिय कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक और इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा (TTP) के बीच संबंध पाया गया है।

परिचय

- TTP एक दुर्लभ और गंभीर रक्त विकार है, जो पूरे शरीर में छोटी रक्त वाहिकाओं में छोटे रक्त के थक्के (थ्रोम्बी) के निर्माण की विशेषता है।
- थक्के मस्तिष्क, गुर्दे और हृदय जैसे अंगों में रक्त के प्रवाह को सीमित या अवरुद्ध कर सकते हैं।
- यह प्राय: ADAMTS13 एंजाइम के विरुद्ध ऑटोइम्यून एंटीबॉडी के कारण होता है।
- **लक्षण:** बुखार, थकान और कमजोरी, पीली त्वचा या पीलिया, न्यूरोलॉजिकल लक्षण, पुरपुरा या अस्पष्टीकृत चोट, पेट में दर्द और सांस की तकलीफ या दिल के प्रभावित होने पर दिल की विफलता के लक्षण।
- **उपचार:** जीवित रहने के परिणामों में सुधार के लिए प्लास्मफेरेसिस और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के साथ प्रारंभिक पहचान तथा तत्काल उपचार आवश्यक है।

Source: TH

NGOs का FCRA लाइसेंस निरस्तीकरण

समाचार में

- केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि विकास विरोधी गतिविधियों या जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल किसी भी गैर सरकारी संगठन का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)

- यह विदेशी दान को नियंत्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आंतरिक सुरक्षा से समझौता न करें।
- इसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था और 2010 में सख्त नियमों के साथ इसमें संशोधन किया गया था।
- **प्रयोज्यता(Applicability):** FCRA विदेशी दान चाहने वाले सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है। गैर सरकारी संगठनों को FCRA के तहत पंजीकरण कराना होगा, प्रारंभिक पंजीकरण पाँच वर्षों के लिए वैध होगा, यदि वे अनुपालन मानदंडों को पूरा करते हैं तो इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- **FCRA आवश्यकताएँ:** विदेशी दान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों या व्यक्तियों को FCRA के तहत पंजीकरण कराना होगा, दिल्ली में SBI में एक निर्दिष्ट बैंक खाता खोलना होगा और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।
    - निधियों को किसी अन्य NGO को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग अधिनियम की शर्तों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।

- **अनुमत उद्देश्य(Permitted Purposes):** पंजीकृत संघ सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विदेशी योगदान का उपयोग कर सकते हैं। वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
- **2015 में नए नियम:** गैर सरकारी संगठनों को यह घोषणा करनी होगी कि विदेशी धन भारत की संप्रभुता, अखंडता, मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंधों या सांप्रदायिक सद्भाव को हानि पहुँचाएगा।
  - उन्हें सुरक्षा एजेंसियों के लिए वास्तविक समय की पहुँच प्रदान करने के लिए कोर बैंकिंग वाले बैंकों का उपयोग करना चाहिए।
- **दान प्राप्त करने से प्रतिबंधित संस्थाएँ:** विधायक, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और मीडियाकर्मी विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर सकते।
- नए FCRA नियमों के तहत, राजनीतिक दल, विधायक, चुनाव उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और मीडिया हाउस(सभी को सामान्यतः विदेशी योगदान से प्रतिबंधित किया जाता है) अगर वे विदेश में अपने रिश्तेदारों से विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं और 90 दिनों के अंदर सरकार को सूचित करने में विफल रहते हैं, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हालाँकि, उन्हें प्राप्त विदेशी योगदान पर 5% जुर्माना देना होगा।
- **निगरानी:** केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) FCRA के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
  - मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी दान को नियंत्रित करता है।
  - NGO को विभिन्न कार्यक्रमों (सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आदि) के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना होगा।
- **पंजीकरण का निलंबन या निरस्त करना:** निदेशक (FCRA) के नोटिस में कई शर्तें बताई गई हैं, जिनके तहत NGO पर कार्रवाई की जा सकती है, जिनमें शामिल हैं:
  - विकास विरोधी गतिविधियों या विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए विदेशी धन का उपयोग।
  - संगठन या उसके पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के साक्ष्य।
  - आतंकवादी या कट्टरपंथी संगठनों से संबंध।
  - जबरन धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण में शामिल होना।
  - NGO की इच्छित परियोजनाओं के लिए विदेशी निधियों का उपयोग करने में विफलता।

Source : IE

सेवा कार्यक्रम के रूप में EV

सन्दर्भ

- केंद्रीय विद्युत मंत्री ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के 'ईवी एज़ ए सर्विस' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
  - CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की सहायक कंपनी है।

'EV एक सेवा के रूप में' कार्यक्रम

- इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में EVs की बढ़ती मांग को पूरा करना है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले दो वर्षों में 5,000 ई-कारें तैनात करना है।
- **लचीला खरीद मॉडल:** यह कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के ई-कार ब्रांड/मॉडलों को तैनात करने की अनुमति देता है, जिससे सरकारी कार्यालयों को अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम ई-कार चुनने में सहायता मिलती है।

- **महत्व:** 'ईवी एज़ ए सर्विस' का शुभारंभ हाल ही में पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरूआत के बाद हुआ है, जो एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देना है।

पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE)योजना

- इसका तात्पर्य है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE)।
- PM E-DRIVE भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण के दूसरे चरण (फेम इंडिया दूसरे चरण) का स्थान लेगा।
- भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) दो वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ नई योजना को लागू करेगा।
- योजना इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। निजी या साझा गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिक कारों को इस नई योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा।
- सरकार ने योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए EV खरीदारों के लिए ई-वाउचर प्रस्तुत किए हैं।
  - ये वाउचर खरीद के समय बनाए जाएंगे और आधार के माध्यम से प्रमाणित किए जाएंगे, जिससे सब्सिडी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

Source: PIB

होकरसर आर्द्रभूमि (Hokersar wetland)

सन्दर्भ

- कश्मीर घाटी में होकरसर आर्द्रभूमि में कम वर्षा के कारण पानी की कमी हो गई है, जिससे प्रवासी पक्षियों का आगमन प्रभावित हो रहा है।

परिचय

- **अवस्थिति:** कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य और झेलम नदी बेसिन में स्थित है।
- **जल विज्ञान स्रोत:** अभ्यारण्य को दो बारहमासी इनलेट धाराओं द्वारा पोषित किया जाता है; पूर्व से दूधगंगा और पश्चिम से सुखनाग नाला।
- **महत्व:** यह एक रामसर साइट है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में अपनी भूमिका के कारण इसे कश्मीर के "अंतर्राष्ट्रीय पक्षी हवाई अड्डे" के रूप में भी जाना जाता है।
- **जीव:** यह साइबेरिया, चीन, मध्य एशिया और उत्तरी यूरोप से आने वाले 68 जलपक्षी प्रजातियों जैसे कि लार्ज इग्रेट, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, लिटिल कॉर्मोरेंट, कॉमन शेल्डक, टफ्टेड डक और लुप्तप्राय व्हाइट-आइड पोचर्ड के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- **वनस्पति:** यह आर्द्रभूमि कश्मीर के बचे हुए रीडबेड वाला एकमात्र स्थल है।
  - जलीय वनस्पतियों में टाइफा, फ्राग्माइट्स, एलोचारिस, ट्रैपा और निम्फोइड्स जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं, जो उथले से लेकर खुले पानी वाले क्षेत्रों तक के परिसर बनाती हैं।

आर्द्रभूमि के सामने चुनौतियाँ

- **कम वर्षा:** प्राथमिक चिंता का विषय है जिसके कारण जल स्तर में कमी आती है, जिससे पक्षियों का प्रवास प्रभावित होता है।
- **अवैध रेत खनन:** प्राकृतिक परिदृश्य और जल प्रवाह में बाधा डालता है।

- **अतिक्रमण:** मानवीय गतिविधियों ने आर्द्रभूमि क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, जिससे इसका प्रभावी आकार कम हो गया है।

Source: DTE

डिक्लिपटेरा पॉलीमोर्फा (Dicliptera Polymorpha)

समाचार में

- वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट में डिक्लिप्टेरा की एक नई अग्निरोधी, दोहरे प्रस्फुटन वाली प्रजाति की खोज की है।

डिक्लिपटेरा पॉलीमोर्फा के बारे में

- यह एक असामान्य दोहरे प्रस्फुटन का पैटर्न प्रदर्शित करता है, जो वर्ष में दो बार खिलता है: पहला मानसून के बाद (नवंबर की शुरुआत से मार्च या अप्रैल तक) और फिर मई एवं जून में घास के मैदानों में आग लगने के बाद।
- स्पाइकेट पुष्पक्रम वाली एकमात्र ज्ञात भारतीय प्रजाति; इसकी सबसे करीबी रिश्तेदार अफ्रीकी प्रजातियाँ हैं।
- यह सूखे और आग जैसी कठोर जलवायु में भी पनपता है, तथा इसकी अद्वितीय पायरोफाइटिक स्वभाव प्रदर्शित करता है।

Source: DST

■■■■